यही था कि इस मिल को जिस सिस्टम से, उसकी जमीन को बेचना है, वह आप बेच डालें। इसमें हमको पूर्ण अधिकार है जैसे भी बेचना है। इसमें फुल ट्रासपेरेन्सी के साथ बेचना है, लेकिन जहां तक मुम्बई का है, अर्बन इलाका है, शहर के मध्य में है, इसलिए बड़े बड़े माल या मल्टी-स्टोरीज हों, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। टैक्सटाइल पोस्चर के साथ इसमें बहुत हैंडीक्राफ्ट माल हो, फाइबर मार्केट हो, क्लॉथ मार्केट हो, बड़े बड़े वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा हो, इस जमीन का अच्छा उपयोग हो, जैसे यहां दिल्ली में प्रगति मैदान है, वैसा ही मुम्बई में भी कोई मैदान हो, जिसमें मशीनरी रखना हो या मशीनरी शो करना हो, वह कर सके, व्यापार करना हो वह कर सके। इस हिसाब से यह प्रोजेक्ट हमारी सीधी देखरेख में इंपलीमेंट होंगे। इसमें कोई प्राइवेट बिल्डर मकान बनाकर या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके सीधा मुनाफा करे, उस हक में हम नहीं हैं।

Textiles Exports

*202. SHRI B.J. PANDA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that he had made a statement that our exports will double in the next two years quelling fears that cheaper Chinese products will hit the Indian industry;

(b) how far we will benefit from the free global trade in the textile market; and

(c) what is our action plan to put thrust on making the "Made in India" brand popular in the world market?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI SHANKERSINH VAGHELA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes, Sir. There is a general perception that India's textile exports would increase in the post quota regime starting from 1st January 2004. According to a recent study by CRISIL (commissioned by Indian Cotton Mills Federation), the India's textile and clothing industry has the potential to double the country's share of the global textiles and clothing market to 6 per cent, implying export earnings of US$ 40 billion by 2010.

The free global trading regime would result in increased international trade in textiles thus providing greater export opportunities for the indigenous textile industry. At the same time, it will expose the domestic

industry to increased competition in the international market. The industry will have to improve its efficiency and productivity to meet the emerging global competition.

(c) Government is already operating a Brand Equity Fund Scheme to promote Indian brands in overseas market with the primary objective of brand promotion. The scheme is also making the "Made in India" label a symbol of quality, competitive price, reliability and service to the customer.

The Central assistance under the scheme is provided for the following activities:

*To finance the activities linked to the objective of brand promotion as distinct from export promotion.

*Undertake international promotions to project India as a whole as well as specific production sectors *viz.*, Industry, agriculture, services etc.

*Support sectoral promotions: e.g., within industry, specific industries like engineering, textiles, electronics, pharmaceuticals, softwares etc.

*Support product group promotion within each sector: *e.g.*, within engineering products, segments like cycles, automobiles etc.

*Support particular brands which have achieved world class quality and performance standards.

*Support domestic awareness generation programme directed at quality and high business ethics.

The scheme is also applicable to promotion of India's apparel and textile brand in the markets abroad.

In addition, the Export Promotion Councils have been undertaking export promotion events like participation in overseas exhibitions/fairs, organizing BSMs abroad, overseas publicity, sponsoring trade delegations etc. in consultation with Indian Missions abroad to improve the brand image of Indian Textiles.

SHRI B.J. PANDA: Sir, I think there is an error in the hon. Minister's answer which gives the impression that the quota regime has already been removed eleven months ago. In my understanding, I think, it is only going to be removed from the first of the next month. Anyway, that is

typographical error. My first supplementary question is this. The hon. Minister has stated that this free global trading regime will expose the domestic industry to increased competition, which will have to improve its efficiency and productivity. My question is this: What are the steps that his Ministry is taking to help improve the competitiveness of the Indian textile industry?

श्री शंकर सिंह वाघेला: चेयरमैन साहब, यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है। इस पर होमवर्क हमने तकरीबन मिनिस्टरी का चार्ज लेते हुए किया कि जनवरी, 2005 तक कोटा रिजीम पूरः होना है और इंडियन टैक्सटाइल सेक्टर को बड़ा जम्प एक्सपोर्ट में लेना है और वह जम्प लेने के लिए जो भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसके लिए आते ही हमने बजट में फिसकल पालिसी में सेनवेट रिमूव करके या 5 परसेंट मशीनरी को इम्पोर्ट का कंसेशन देते हुए, जो कस्टम एक्साइज ड्यूटी होती है, वह पूरा, इनको और आगे ले जाने के लिए फिसकल पालिसी, बजटरी प्रोवीजन हमने रखें हैं। इसके साथ साथ चेयरमैन साहब, यह तो तब की स्कीम है, इसमें 20 हजार करोड़ का आज हमने डिस्पोजल कर दिया है। इतना ही नहीं, हमारी क्वालीटी अच्छी बने, इसलिए अपरेल पार्टस, टीसीआईडी स्कीम, इसमें और इन्फ्रारस्ट्रक्चर की सुविधा का प्रोवीजन इसमें है और जो टेक्नोलोजिकल मिशन है, टीएमसी, कॉटन की अच्छी क्वालिटि जिनिंग और प्रेसिंग में हो, यार्न अपने अच्छे हों, इसलिए इन टोटल आने वाले दो साल में तकरीबन 26 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट हो, इस हिसाब से होमवर्क हमारा हो रहा है। इस हिसाब से हमारा होम वर्क हो रहा है और कल ही प्रधानमंत्री जी ने जो हिसाब-किताब मांगा था कि आने वाले दिनों में आप क्या कर रहे हैं, इसी सिलसिले में पूरा प्रेजेंटेशन हमने दिया है।

SHRI B.J. PANDA: Sir, my second supplementary question is that India has a window of opportunity of two years, after which the Chinese will also be allowed to trade freely and their industry is far larger than ours. So, in this light, I would like to know this: The hon. Minister has stated that the Textile Ministry is also availing of the brand equity fund scheme to promote Indian brands. I would like to have an answer as to which are India's apparel and textile brands which have taken advantage of this scheme and how much funds have been sanctioned for promoting the Indian textile brands and apparels.

श्री शंकर सिंह वाघेला: चेयरमैन सर, कामर्स मिनिस्ट्री मेड इन इंडिया ब्रांड इम्प्लिमेंट कर रही है, तकरीबन 200 करोड़ का इसका बजट है। फिर इंटरनेट पर जाना है, ऐडवरटाइजमेंट देना है और क्या-क्या करना है, इसकी बहुत डिटेल है, मैं उसे पढ़कर आपका और सदन का समय बर्बाद करना

नहीं चाहूंगा। रिटन स्टेटमेंट अगर आप चाहेंगे तो मैं दे दूंगा। जहां तक चाइना का सवाल है, यह थ्रेट सिर्फ इंडिया को नहीं है। हमको बहुत ज्यादा थ्रेट है क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में सबसे ज्यादा डम्पिंग चाइना का हो रहा है, हमारे यहां भी हो रहा है, लेकिन चाइना का और हमारा जहां तक कम्पेरिज़न है, हम कई बातों में चाइना से थोड़े अलग होते जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपने सही फरमाया कि चाइना की एंट्री डब्ल्यू॰टी॰ओ॰ में 2008 में होगी, लेट होगी, इसलिए हमारे कम्पीटीशन में चाइना 2008 में आएगा। तब तक इनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, वे रिस्ट्रिक्शंस रहेगी। इसका लाभ लेते हुए हमको आने वाले दिनों में चाइना के जो माइनस प्वाइंट्स हैं और हमारे जो प्लस प्वाइंट्स हैं, इनको मिलाकर कैसे एक्सपोर्ट और बढ़ाया जाए, उसकी हम चिंता कर रहे हैं। उदाहरण के लिए लेबर प्राब्लम है, अभी चाइना के ऊपर भी लेबर लॉज लगने जा रहे हैं। पावर की प्राब्लम हमारे यहां है, वहां पावर की इतनी प्राब्लम नहीं है। इनका जो कंट्रोल्ड इकनॉमिक करंसी ओवर वेल्यू करते हैं, इसके ऊपर अमेरिका चिंता कर रहा है कि आप अपनी इकॉनमी भी लैवल करिए। चाइना के लोग इन्वेस्टमेंट सब्सिडी और दे रहे हैं, हम उतनी नहीं दे रहे हैं। इसलिए कई बातों में चाइना हमसे बहुत आगे है और न सिर्फ टैक्सटाइल में किसी भी प्रोडक्शन में डम्पिंग पूरी दुनिया में हो रहा है । जहां तक हमारी मिनिस्ट्री का सवाल है, टैक्सटाइल एक्सपोर्ट का सवाल है, चाइना के मुकाबले हमारे क्या प्लस हैं और उनके माइनस हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए आने वाले दो साल में एक्सपोर्ट, जो आज तकरीबन 13 बिलियन डॉलर है, उसके 26–30 बिलियन डॉलर होने की संभावना है।

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, I think, this is pertaining to the multi-fibre agreement. This multi-fibre agreement will come into force from March, 2005. Sir, how are you planning to prepare the country to face this new challenge which will come up at the commencement of this agreement?

श्री शंकर सिंह वाघेला: सर, मेरा वही जवाब है, रेपिटीशेन है कि फिस्कल डयूटी रिफार्म प्रोसैस को स्टेब्लाइज़ करने का सोचा है, जो इस बजट में हमने किया था। इतना ही नहीं बैंक जो हो, प्रोऐक्टिव हो इस इंडस्ट्री में। पहले बैंक वाले टैक्सटाइल सैक्टर को लोन नहीं देते थे, लेकिन आज हमारी टफ्स की स्कीम के नीचे बैंकों ने 20 हजार करोड़ रुपए का डिस्पोज़ल किया है, लोन देने में। हमारा जो 5 परसैंट इंटरेस्ट सब्सिडी का है, जो हमारे प्रोसैसिंग यूनिट के 20 भाग हैं, इनको 5 परसेंट से 8 परसेंट इंटरेस्ट की सब्सिडी देने का भी प्रोविजन हमने सोचा है और आने वाले दिनों में जो निटिंग सैक्टर एस॰एस॰आई॰ है, इनको डि-रिज़र्व करने का भी हमने सोचा है, इससे भी हमने सोचा है कि बहुत एक्सपोर्ट होगा। स्माल इज़ ब्यूटीफुल का समय अब पूरा हो गया है, अब तो लार्ज सैक्टर को कम्पीट करने के लिए मोर प्रोडक्शन, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर फारेन एक्सचेंज अर्निंग, इन सबके बारे में हमारा होम वर्क हुआ है और इसकी डिटेल मैंने आपको बताई है। टफ्स, टीएनसीए,

टीसीआईडीसीए, एपीए आदि बहुत स्कीम्स हमने इम्प्लिमेंट की हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि बहुत दिनों से भारत इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि सन् 2005 में टैक्सटाइल का कोटा रिजीम खत्म हो जाए ताकि हम बहुत बड़ी मात्रा में अपना टैक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ा सकें, लेकिन कुछ देश जो आज इस कोटा रिजीम से लाभान्वित हो रहे हैं, वे इस कोशिश में लगे हैं कि यह कोटा रिजीम खत्म न हो। मेरी एक प्रमाणिक जानकारी है कि सितम्बर माह में जेनेवा में उन देशों की अलग एक बैठक हुई थी, जिसमें वे यह रणनीति बना रहे थे कि भारत इससे लाभान्वित होगा, इसलिए कोटा रिजीम खत्म न हो, इससे भारत और चीन दोनों लाभान्वित होंगे। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि क्या आपको इस तरह की जानकारी है कि कुछ देश इस कोशिश में लगे हैं कि यह कोटा रेजीम खत्म न हो, और अगर जानकारी है, तो उनकी कोशिशों को नाकाम करने के लिए भारत क्या कर रहा है?

श्री शंकर सिंह वाघेला: सभापति जी, मैडम का यह जो प्रश्न है, मैं समझता हूं कि now it is history उन्होंने कोशिश जरूर की थी, हमारे ऑफिसर्स वहां गये थे, किन्तु उन्होंने बिल्कुल डिनाइ कर दिया, यह कोटा रेजीम खत्म होना चाहिए और खत्म हो गया है। अब कोई हर्डल नहीं बचे हैं। आज दिसम्बर की पंद्रह तारीख है और अब पंद्रह दिन बचे हैं। पंद्रह दिन में शत-प्रतिशत कोटा रेजीम खत्म होने में कोई भी ऑब्स्टेकल आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा, जो आपने कहा है चाइना 2008 में, चाइना की डब्लू॰टी॰ओ॰ के नीचे लेट एंट्री थी इसलिए इनके ऊपर रैस्ट्रिक्शन तीन साल तक और रहेंगे। इसलिए हमारा कोटा....,... ।

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है, आपका कोटा अब खत्म हो रहा है। श्रीमती सरला माहेश्वरी।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: माननीय सभापति जी, मुक्त वस्त्र बाजार में भारत के लिए जो अकूत संभावनाएं खुली हैं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि इन अकूत संभावनाओं को देखते हुए क्या आपने चीन के अनुभवों का अध्ययन किया है? जहां तक हमें जानकारी है, यह पता चलता है कि चीन आज वस्त्र निर्यात के मामले में अग्रणी इसलिए है क्योंकि वहां कपड़ा बनाने की जो मिलें हैं, उन मिलों को वस्त्र निर्माण के साथ जोड़ दिया गया है और इसलिए वे मिलें वस्त्र निर्माण के संदर्भ में, वस्त्र निर्यात के संदर्भ में जो अकूत संभावनाएं हैं, उसमें वे प्रतिद्वन्द्वी ठहर रही हैं।

श्री सभापति: क्वेश्चन, क्वेश्चन।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति जी इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि इन संभावनाओं को देखते हुए और चीन के अनुभवों को देखते हुए, जो बंद मिलों का सवाल था, क्या हमारे देश में आप इस तरह की कंपोज़िट इकाइयों को बनाने पर विचार कर रहे हैं क्योंकि आज के

ज़माने में कपड़े की जो लागत है, वह रुई के उत्पादन के साथ शुरू होती है?

श्री सभापति: बस बस हो गया, जमाने की बात मत करो, क्वेश्चन का जवाब दो।

श्री शंकर सिंह वाघेला: सभापति जी, यह मैडम का प्रश्न है अभी मैंने जवाब दिया कि चाइना बिल्कुल लेटेस्ट मशीनरी के साथ, अल्ट्रा मॉडर्न मशीनरी के साथ मैन्युफैक्चर कर रहा है। किन्तु हमारी आउट ऑफ डेट मशीनरी है, जो कई साल पुरानी है। अत: मशीनरी में मॉडर्नाइज़ेशन करने के लिए हमने कस्टम मशीनरी इम्पोर्ट करने में पांच प्रतिशत....

श्रीमती सरला माहेश्वरी: खाली मॉडर्नाइज़ेशन का सवाल नहीं है, मेरा सवाल दूसरा है।

श्री सभापति: अब आप इनको बोलने तो दीजिए।

श्री शंकर सिंह वाघेला: देखिए यह कपड़ा और वस्त्र का सवाल नहीं है। हमारे यहां डीसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री है, रेडीमेड कपड़ा बनाने वाले अलग हैं, कपड़ा बनाने वाले अलग हैं, मिल्स वाले अलग हैं, एक नहीं हैं। चाइना की जो पालीटिकल सिचुएशन है, वे कुछ भी कर सकते हैं। उनको कोई नहीं रोकता है। हमारे यहां जो मिलों पर कपड़ा बनाता है, उसे हम नहीं कह पाएंगे कि आप रेडीमेड गार्मेंट भी बनाइए। रेडीमेड गार्मेंट्स की दुनिया अलग है, कपड़े की दुनिया अलग है, सबकी दुनिया अलग है।

श्री सभापति: चलिए, चलिए, हो गया।

Increased vigil by coast guard along Kerala Coast

*203. SHRIMATI S.G. INDIRA:†
SHRI N.K. PREMACHANDRAN:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Coast Guard has stepped up vigil along the coast of Kerala following a tip off about an unidentified vessel carrying arms from the Gulf;

(b) if so, the details thereof

(c) whether it is also a fact that the Coast Guard had increased its surveillance along the Kerala coast in the last few days; and

(d) if so, the details thereof?

---

† The Question was actually asked on the floor of the House by Shrimati S.G. Indira.